



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसागरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 1974/चैत्र 25, 1896

N.O. 181]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 1974/CHAITRA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April 1974

S.O. 248(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Karnataka is hereby published:—

ORDER No. 12

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), we hereby determine, on the basis of the latest census figures and having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Karnataka as twenty-eight (28) of which 4 seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly

of the State as two hundred and twenty-four (224) of which 29 seats shall be reserved for the Scheduled Castes and 2 seats for the Scheduled Tribes.

J. L. KAPUR, Chairman.
TARUN KUMAR BASU, Member.
T. SWAMINATHAN, Member.

[No. 282/74(2)]

By order,

P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1974

का० ग्रा० 248(अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन कर्नाटक राज्य के बारे में किया गया आदेश एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश सं० 12

परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में हम, नर्बनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तथा संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 तथा 332 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य को लोक सभा में आवंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या अठाईस (28) जिनमें से 4 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे तथा इस राज्य की विधान सभा के लिए समनुदेशित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या दो सौ चौबीस (224) जिनमें से 29 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 2 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे, एतद्वारा अवधारित करते हैं ।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष ।

तारुन कुमार बसु, सदस्य ।

ति० स्वामीनाथन, सदस्य ।

[सं० 282/74(2)]

आदेश से,

पी० आई० जेकर, सचिव ।